

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI
OBJECTION BY APPLICANT**

In
ORIGINAL APPLICATION NO. 1322 OF 2024

IN THE MATTER OF

Rajneesh Karnwal

APPLICANT IN PERSON

Versus

Union of India through Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate
Change and ors.

RESPONDENTS

INDEX

S.No	Particulars	Page No.
1.	Objection by Applicant	1-3
2.	Affidavit	4
3.	Annexure 1	5-6
4.	Annexure 2	7
5.	Annexure 3	8-9
6.	Annexure 4	10
7.	Annexure 5	11-17

Date : 08/07/2025
Place : Meerut

Rajneesh Karnwal
Applicant in Person



BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

OBJECTION BY APPLICANT

In

ORIGINAL APPLICATION NO. 1322 OF 202

IN THE MATTER OF

Rajneesh Karnwal

APPLICANT IN

Versus

Union of India through Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate
Change and ors.



RESPONDENTS

OBJECTION BY APPLICANT

MOST RESPECTFULLY SHOWETH;

I, Rajneesh Karnwal aged about 39 years R/O B-17, Main Road Hastinapur UP hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That on behalf of the Joint Committee, the District Magistrate, Meerut, filed an affidavit dated 17th March 2025, which was subsequently uploaded on the official website of the Hon'ble National Green Tribunal (NGT) on **20th March 2025**.
2. That according to the affidavit, **Point No. 5 (at Page No. 31)** states

It is also submitted that the land in question belongs to private individuals as per the Report of the SDM, Mawana. Which has been attached to the Joint Committee Report as Annexure 2.

In this no any Khatauni submitted by the DM Meerut in support of the reply. But According to **Hastinapur Pandavan Khatauni Fasli Year 1360** wherein the land presently claimed as

private is, in fact, recorded as government land. Moreover, the said land forms part of the Budhi Ganga River. Refer Annexure 1.

3. That In **Annexure 1, Page 33, Point No. 3**, it is mentioned that:

No illegal construction observed on any forest land or government land as per records/maps provided by field staff of forest and revenue department.

This point is also in direct contradiction to the revenue records of **Hastinapur Pandavan Khatauni Fasli Year 1360**, wherein the land presently claimed as private is, in fact, recorded as government land. Moreover, the said land forms part of the Budhi Ganga River and, as such, is not subject to private ownership, in accordance with various judgments of the Hon'ble Supreme Court of India, which have consistently held that riverbeds and water channels are public property and cannot be privately owned or transferred. Khatauni Fasli Year 1360 of Hastinapur Pandavan is attached herewith **Annexure 1**.

4. That the Joint Committee has failed to perform its duties in accordance with the directions issued by the Hon'ble Tribunal, thereby violating the mandate and scope of inquiry entrusted to it.

5. That the affidavit submitted before the Hon'ble Tribunal contains incorrect and misleading information and does not reflect the factual position on the ground.

6. That a news report was published in *Janwani* on **9th May 2025**, which highlights the **illegal mining activities** being carried out. The report exposes violations of environmental norms, illegal extraction of sand and the failure of local authorities to curb such activities. This report serves as independent evidence corroborating the ongoing environmental degradation in the region. A copy of this news article is enclosed as **Annexure 2**.

7. That illegal sand filling operations or construction have been initiated in the area of Hastinapur Pandavan, in blatant violation of environmental norms and without requisite approvals. **Refer Annexure 3**

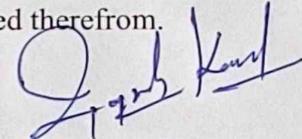
8. That illegal mining operations within the Hastinapur Wildlife Sanctuary have led to the removal of large sand mounds near Saifpur Firozpur, District Meerut, thereby causing significant ecological disturbance and violation of protected area regulations. Refer satellite image of 17 Jan 2025 **Annexure 4**
9. That on **28th April 2025**, the Applicant submitted a **Written Statement** regarding **illegal tree felling** and other unauthorized activities being carried out within the **Hastinapur Wildlife Sanctuary**. A copy of the email is annexed herewith and marked as **Annexure 5**.

For all the reasons stated above the Hon'ble Tribunal may kindly be pleased to take cognizance of all these facts and to pass appropriate orders to meets the ends of Justice and equity.

AND FOR THIS ACT OF KINDNESS THE APPLICANTS, AS IN DUTY BOUND, SHALL EVER PRAY.

Verification

Verified on this 8 day of July 2025 that the contents of the present Application are true and correct to my knowledge and belief and nothing material is concealed therefrom.



Rajneesh Karnwal

Applicant in Person

Date: 08/07/2025

Place: Meerut



Shyam Singh
ATTESTED 8/7/25
 Shyam Singh Advocate
 Public Notary Mawana

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 1322 OF 2024

IN THE MATTER OF

Rajneesh Karnwal

APPLICANT IN PERSON

Versus

Union of India through Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate
Change and ors.

RESPONDENTS



Affidavit

I, Rajneesh Karnwal aged about 39 years R/O B-17, Main Road Hastinapur UP do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That I am the Applicant/Applicant In Person in above mentioned application and I am fully conversant with the facts and circumstances of the case and therefore competent to swear this affidavit.
2. That, the statements made in paragraphs 01 to 09 of this affidavit is true to my knowledge

Applicant In Person

VERIFICATION

Verified on this 8 day of July 2025 that the contents of the present Application are true and correct to my knowledge and belief and nothing material is concealed therefrom.

Applicant In Person

/Deponent

ATTESTED
Shyam Singh Advocate
Public Notary Mawara

ANNEXUR 2

www.dainikjanwani.com

www.dainikjanwani.com

जिम्मेदार मौन, धरती का सीना छलनी कर रहे माफिया

अधिकारी ही खनन माफियाओं को दे रहे संरक्षण, सूरज ढलते ही क्षेत्र में कई जगहों पर शुरु हो जाता है खनन

● जवाणी खादवाता हस्तनपुर

इलाक़े में खनन माफिया बेसीफ़ धरती का सीना चौरकर खनन कर रहे हैं। खनन माफिया ने कई किलोमीटर के दायरे में खनन कर जंगलों में गड्ढे कर दिए हैं। ग्रामियों ने अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई के लिए स्थानीय ग्रामियों ने कई बार उच्चाधिकारियों को शिकायतें पत्र भेजा है। इसके बाद भी जिम्मेदार इस मामले में मौन साधे हुए हैं। इससे खनन माफिया के लैसले बुलंद हैं।

अवैध रूप से हो रहे खनन को लेकर कई बार अधिकारियों को अवगत भी कराया गया, लेकिन उनके आदेशों की अचोखला अधिकारी करते दिखाई दे रहे हैं और घड़ल्ले से जंगलों चल रही है। जबकि कई बार लोगों को शिकायत के बावजूद सम्मवार् जस को तस बन्ने हुई है। उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को लपरता और मिलीभगत के चलते क्षेत्र में अवैध खनन का कारोबार व्यापक पैमाने पर फलफूल रहा है। इसके चलते खनन माफियाओं ने हस्तनपुर के अस्तित्व के जंगलों से लाखों रुपये को खन सड़ता नष्ट कर दी। खन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलीभगत से खन सड़ता के साथ कई प्रजाति के पेड़ भी नष्ट कर डाले। साबका और शासन-प्रशासन के आदेशों को धाड़ ब्रजते हुए खनन माफिया धरती का सीना छलनी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अवैध खनन के आरोधारी में लिप्त लोगों पर कार्रवाई करने के प्रजाय जिम्मेदार विभाग के अधिकारी साब-पर-साब धरे बैठे हैं। रात के



अंधेरे में खनन माफिया खादर क्षेत्र के कई गाँव में अवैध खनन का कारोबार जारी है। लोगों का कहना है कि खनन माफियाओं को नेताओं के साथ जिम्मेदार विभाग अधिकारियों का संरक्षण मिला हुआ है। मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ ने फरमान जारी किया था कि अवैध खनन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, लेकिन एकीकृत इससे कोसें दूर है।

हस्तनपुर धाना क्षेत्र के गाँव गडोड़, राठोड़ा, तारापुर, सैफपुर-कर्मचंदपुर, नजपुर, माणपुर, झखवा आदि के जंगलों में बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया रहा है। सता पक्ष के ही कुछ नेताओं का इन खनन माफियाओं को संरक्षण मिला हुआ है। दिन-

हवा में उड़ गए एनजीटी के आदेश!

एनजीटी के आदेशों को पूरी तरह हवा में उड़ते हुए खनन माफिया, पुलिस, प्रशासन और खनन विभाग तीनों से सटिंग कर घड़ल्ले से अपना काम कर रहे हैं। क्षेत्र में बन रही कॉलोनियों में धरात के नाम पर राती-रात खनन कर सैकड़ों टूटियां, डंपर सड़कों पर दौड़ रहे हैं। बताया जाता है कि अवैध मिट्टी खनन की शिखरों लोगों ने कई बार जिम्मेदार अधिकारियों से की, लेकिन खनन माफिया पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस कारण खनन माफिया भराव के नाम पर टैका से रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि देहात क्षेत्रों में मिट्टी के अवैध खनन का कारोबार बड़े स्तर पर चल रहा है। दिनभर सड़कों पर मिट्टी से भरे डंपर दौड़ते रहते हैं। हस्तनपुर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है। इतना ही नहीं अनुमति से दोगुना स्थानों पर अवैध खनन और दो भी जेसीबी से किया जा रहा है। यही नहीं जितनी गहवाई तक खुदाई की अनुमति मिलती है, उससे दोगुना से ज्यादा खुदाई करने के चारुा बहुत स्थानों पर खंड बन गई है।

रात खनन माफिया ने राठोड़ा तारापुर के बीच जमकर खनन किया। ग्रामियों ने खनन बंद सूचना राजस्व विभाग के अधिकारियों सहित धाना पुलिस और खनन अधिकारों

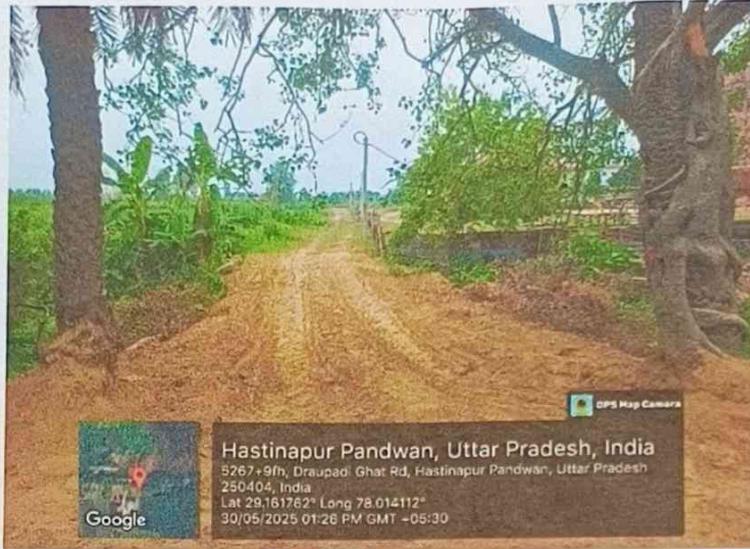
आकाओं की मिलीभगत से

चल रहा अवैध खनन का खेल अवैध खनन को सतपरती में इन दिनों मिट्टी के अवैध खनन का धाड़ पबान पर है। खनन माफिया धरती का सीना छलनी कर अवैध कॉलोनियों में भराव कर रहे हैं। खनन कबड़े के हवाज जेसीबी से ड्रे रहा है, अनुमति से अधिक स्थानों पर हो रहा है, इतने गहवाई तक खुदाई की अनुमति है, उनके दोगुना खोदा जा रहा है और यह एक राजनीतिक और कुछ प्रभावशाली लोगों की मिलीभगत से चल रहा है। पुलिस प्रशासन के अवैधकारियों तक जो इस बात की सूचना होने के बावजूद अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई खनन माफियाओं के खिलाफ नहीं की गई है।

को दी। खनन माफिया से मिलीभगत के चलते खनन अधिकारों, धाना पुलिस या राजस्व को टीम मॉके पर नहीं पहुंची, जिसके चलते खनन माफिया ने रात भर जमकर खनन सरकारी खजाने को लाखों को चपत लगाई। खनन के लिए तहसील में तैनात खनन अधिकारी मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ के आदेशों का जमकर उल्लंघन करते हैं। ग्रामियों को फोन उठाना तो दूर की बात है, यदि कोई खनन अधिकारी के नंबर पर लगातार फोन करता है, तो उसका नंबर भी ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया जाता है। मामले में एसडीएम मवाना दोपकनाथर का कहना है कि रात को खनन को जानकारी पर धाना प्रभारी को खनन रुकवाने के लिए कहा गया था, लेकिन धाना पुलिस के मौके पर न पहुंचने को जानकारी मिली है। मामले में कार्रवाई की जाएगी।

True Copy
Rajesh Kumar

ANNEXURE 3

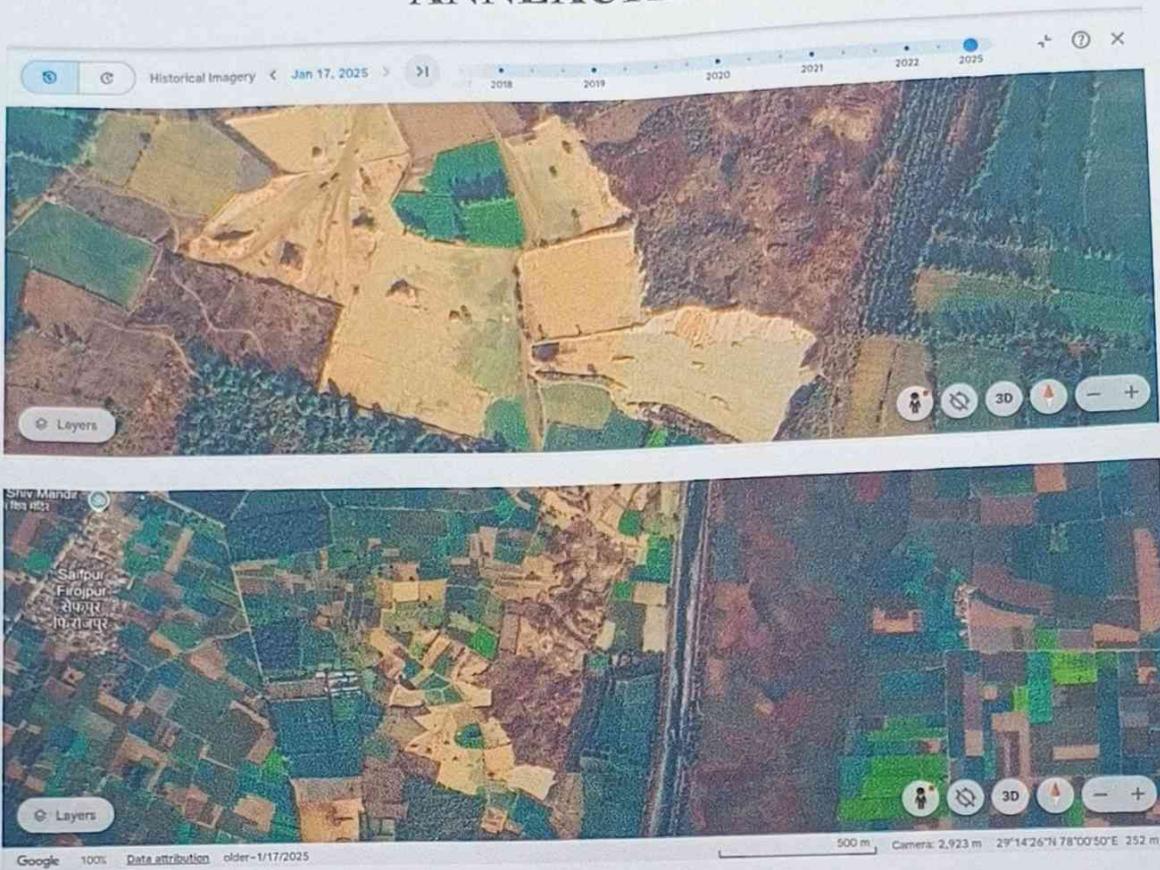


Tove Copy
Rajiv Kaul



True Copy
S. S. S. S.

ANNEXURE 4



True Copy
Safpur, Kaul

ANNEXURE 5

← 📎 🕒 🗑️ 📧 📧 ⋮ 1 of 7 < >

Written Submission in the Matter of Rajneesh Karnwal vs Union of India and ors OA 1322 of 2024 🖨️ 📧

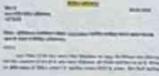
R RAJNEESH KARNWAL <rajneeshkarnwal24@gmail.com>
to judicial-ngt, secy-moef, psecforest-up, dmmee, dfomeerut@gmail.com ▾

📧 Mon, Apr 28, 10:13 AM ☆ 😊 ↶ ⋮

Respected Sir/Madam,
Pl. refer attachment.

Applicant
Rajneesh karnwal

One attachment • Scanned by Gmail 🕒



True Copy
Rajesh Karnwal

लिखित अभिकथन

28.04.2025

सेवा में,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली

विषय: ओरिजिनल एप्लीकेशन संख्या 1322/2024 रजनीश कर्णवाल बनाम भारत संघ एवं अन्य के संदर्भ में लिखित अभिकथन।

महोदय,

सादर निवेदन है कि मेरठ जनपद स्थित ऐतिहासिक एवं समृद्ध जैव विविधता वाले हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य में हाल ही में अवैध सड़क चौड़ीकरण और निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। दिनांक 27 अप्रैल 2025 को विभिन्न अखबारों में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट के अनुसार, बिना किसी वैधानिक अनुमति के सड़क निर्माण कार्य वन्य जीव क्षेत्र के भीतर हो रहा है, जिससे प्राचीन वृक्षों की कटाई एवं जंगली जीवों के प्राकृतिक आवास को भारी क्षति पहुँच रही है।

यह कार्य सीधे-सीधे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं संबंधित नियमों का उल्लंघन है। यह कार्य न केवल अवैध है, बल्कि हस्तिनापुर की ऐतिहासिक और पारिस्थितिक धरोहर को भी नष्ट कर रहा है।

अत्यंत खेदजनक है कि वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी स्वयं इस अवैध कार्य को जानते हुए भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जब डीएफओ मेरठ यह बयान दे रहे हैं कि मामला उनके संज्ञान में है परंतु कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो रही, तो प्रश्न उठता है कि:

- क्या अब इस तरह से संरक्षित क्षेत्रों को समाप्त कर दिया जाएगा?
- क्या वन विभाग की निगरानी में ही वन क्षेत्र उजड़ने दिए जाएंगे?

जिन अधिकारियों का कर्तव्य वन संरक्षण है, वे स्वयं अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहे हैं। आज वे यहाँ कार्यरत हैं, कल किसी अन्य जिले में चले जाएंगे, परंतु उजड़ा हुआ जंगल पुनः जीवित नहीं हो पाएगा।

विनम्र अनुरोध है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, इस गंभीर मामले में तत्परता से संज्ञान लें।

अतः आपसे निवेदन है कि:

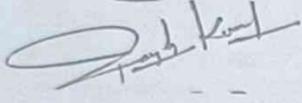
1. हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र में चल रहे अवैध निर्माण कार्यों को तत्काल प्रभाव से रोका जाए।
2. संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।
3. एक उच्च स्तरीय स्वतंत्र जांच कमेटी का गठन कर पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराई जाए।
4. भविष्य में अभयारण्य क्षेत्र में किसी भी कार्य के लिए एनजीटी और अन्य पर्यावरणीय प्राधिकरणों से पूर्व अनुमति अनिवार्य की जाए।
5. उजड़े हुए हिस्सों में पुनः वनीकरण एवं पारिस्थितिक पुनर्स्थापन का कार्य कराया जाए।

आपकी शीघ्र सकारात्मक कार्यवाही से देश की जैवविविधता एवं पर्यावरण को संरक्षित करने में सहायता मिलेगी।

True Copy
[Signature]

भवदीय,

संगलग्न : उपरोक्तानुसार

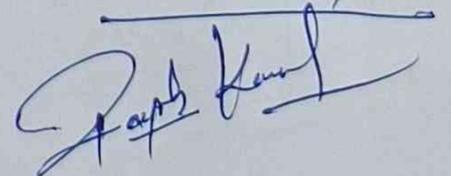


रजनीश कर्णवाल (आवेदक)
मकान नंबर बी/17 मैन रोड
हस्तिनापुर, मेरठ

प्रतिलिपि

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली
2. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, लखनऊ
3. जिलाधिकारी मेरठ
4. डीएफओ, मेरठ
5. एसडीएम मवाना

True Copy



खबरें पुरानी नहीं, छापाता है

शाह टाइम्स

www.shahtimesnews.com



विभिन्न खबरों के लिए QR कोड स्कैन करें।
मुफ्त पर्व E-paper

शेरा, रविवार 27 अप्रैल 2025 पंजाब संस्करण: खं 18 अंक 331 पृष्ठ 12 मूल्य रुपये 5.00

केदार कृपा पत्र 15 विद्युत संख्या 2082

28 फ़ोन 1446 डिजिटल

नई दिल्ली, मुंबई, पटना, इंदौर, कोयंबूर, रायपुर, भुवनेश्वर, बरेilly, मेरठ व उत्तर प्रदेश में प्रकाशित

शाह टाइम्स

मेरठ मेट्रो

मेरठ, रविवार, 27 अप्रैल 2025

वन्य अभयारण क्षेत्र हस्तिनापुर में जिम्मेदार ही करा रहे अवैध कार्य

शाह टाइम्स संवाददाता मेरठ। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार के आरक्षित जंगलों में हो रहा अतिक्रमण रोकने का नाम नहीं ले रहा है। पुराना हस्तिनापुर जंबुद्वीप जैन मंदिर निशिया जी के समीप वन आरक्षित क्षेत्र में सड़क का चौड़ाकरण किया जा रहा है जिससे जंगल के सड़क के नवरोक पेटों का कटान हो रहा है जिससे वन्य जीव विहार का महत्व नहीं रह जाता है। जबकि सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि वन्य जीव विहार के आरक्षित क्षेत्र में किसी भी तरह का अतिक्रमण रोका जाना चाहिए परंतु सरकार के नुमायंदे ही सरकार के नियमों को अनदेखी कर आंख मूंद बैठे हैं।



हस्तिनापुर वन्य जीव विहार लगातार अतिक्रमण की जड़ में जकड़ता जा रहा है। इसी हस्तक्षेप के चलते वन्य जीव प्रभावित हो रहे हैं। आगे दिन बाहर ही हस्तक्षेप और वन्य जीव जंगल में बढ़ते मानवीय हस्तक्षेप के कारण बरिन्दियों की आर रूक कर रहे हैं। ऐसा ही मामला यहां वन्य जीव विहार में जंबुद्वीप से आगे मध्य गंग नहर तक जाने वाले मार्ग पर

चौड़ाकरण कार्य चल रहा है जबकि यह वन्य जीव विहार का आरक्षित क्षेत्र है। कई बार लोगों ने इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों से की परंतु उन्होंने इस तरह ध्यान देना गंवार नहीं समझा।

एक सप्ताह पूर्व ही रूका था कार्य

वन विभाग के अधिकारी स्वयं अपने दूने जाल में स्वयं ही फंसे नजर आ रहे हैं जिस कार्य को वन विभाग ने एक सप्ताह पूर्व ही बिना प्रदेशीय वन्य जीव बोर्ड की अनुमति न होने के कारण बंद करा दिया था। इतना ही नहीं सड़क के चौड़ाकरण करने वाले ठेकेदार को जैसोबी भी रोज कार्यालय पर छोड़ी कर दी गयी

थी तथा वन्य जीव अधिनियम की धाराओं के उल्लंघन के तहत कार्यवाही करते हुए जुर्माना भी वसूला था परंतु अब उसी सड़क के चौड़ाकरण का कार्य धड़ल्ले से प्रारंभ हो गया है परंतु अब उस पर कार्यवाही करने से वन विभाग के अधिकारी गुंज कर रहे हैं।

रसूखदारों के लिए नियम नहीं

उक्त मार्ग जंबुद्वीप से मध्य गंग नहर पट्टी तक लगभग दो किमी का पंच वन्य जीव विहार के आरक्षित क्षेत्र से होकर गुजरता है। जहां भारी संख्या में वन्य जीव निवास करते हैं। वहीं इस जंगल में अवार भी अधिकांश दिखाई देते रहते हैं। वहां

कुछ जैन मंदिर भी इसी मार्ग पर आते हैं तो लोगों का कहना है कि क्या वन विभाग के नियम रसूखदार लोगों पर नहीं लागू होते हैं या फिर केवल आमजनमानस पर ही हंटर चलता है।

पहले भी हुई थी कार्रवाई

लगभग एक दशक पूर्व उपरोक्त रास्ते के समीप ही महाभारत के पितृपद का किरदार निभा रहे कलाकार मुकेश खन्ना को शूटिंग के दौरान वन विभाग ने कैमरे को चिप जब्त कर ली थी। गंगा नदी के भीकूड पुल व अग्रोच रोड को वन विभाग ने संचूरी में बिना अनुमति के निर्माण कार्य पर रोक लगाते हुए ठेकेदार व पीडब्ल्यूडी के

इंजीनियरों को खिलाफ एफआईआर तक करा दी थी। जिस कारण पुल का कार्य अंध में लटका रहा था और वन विभाग की अनुमति के बाद ही पुल पर नियमों के अनुरूप ही कार्य प्रारंभ हो सका था। हस्तिनापुर नगर की ब्लॉक में सामाजिक यानिकी प्रशिक्षण केंद्र के पीछे नाले के निर्माण को भी रूकवा दिया था।

जिला वन अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि यह कार्य पी डब्ल्यू डी द्वारा कराया जा रहा है कड़कर पल्ला झाड़ लिया इस कार्य को परमिशन वन विभाग द्वारा हुई है कि सवाल पर जिला वन अधिकारी ने बात को घुमा दिया लेकिन परमिशन के बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं करी।

True Copy

हस्तिनापुर वन्य आरक्षित क्षेत्र में हो रहा धड़ल्ले से चल रहा अतिक्रमण

शाह टाइम्स संवाददाता मेरठ। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार के आरक्षित जंगलों में हो रहा अतिक्रमण रोकने का नाम नहीं ले रहा है। पुराना हस्तिनापुर जंबुद्वीप जैन मंदिर निशिया जी के समीप वन आरक्षित क्षेत्र में सड़क का चौड़ाकरण किया जा रहा है जिससे जंगल के सड़क के नवरोक पेटों का कटान हो रहा है जिससे वन्य जीव विहार का महत्व नहीं रह जाता है। जबकि सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि वन्य जीव विहार के आरक्षित क्षेत्र में किसी भी तरह का अतिक्रमण रोका जाना चाहिए परंतु सरकार के नुमायंदे ही सरकार के नियमों को अनदेखी कर आंख मूंद बैठे हैं।

हस्तिनापुर वन्य जीव विहार लगातार अतिक्रमण की जड़ में जकड़ता जा रहा है। इसी हस्तक्षेप के चलते वन्य जीव प्रभावित हो रहे हैं। आगे दिन बाहर ही हस्तक्षेप और वन्य जीव जंगल में बढ़ते मानवीय हस्तक्षेप के कारण बरिन्दियों की आर रूक कर रहे हैं। ऐसा ही मामला यहां वन्य जीव विहार में जंबुद्वीप से आगे मध्य गंग नहर तक जाने वाले मार्ग पर



तथा कहते है जिला वन अधिकारी

जिला वन अधिकारी राजेश कुमार ने बड़ा ही हताशास्पद बयान दिया कि जब कार्य रूकवाया गया था। तब अनुमति नहीं थी परंतु अब उन्हें अनुमति प्रदान हो गयी है। परंतु यह समझ से परे है कि अधिकार अनुमति के लिए सालों चलते खली प्रक्रिया एक सप्ताह में कैसे पूरी हो गयी।

अब रूक कर रहे है। ऐसा ही मामला यहां वन्य जीव विहार में जंबुद्वीप से आगे मध्य गंग नहर तक जाने वाले मार्ग पर चौड़ाकरण कार्य चल रहा है। जबकि यह वन्य जीव विहार का आरक्षित क्षेत्र है। कई बार लोगों ने इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों से की परंतु उन्होंने

True Copy

4

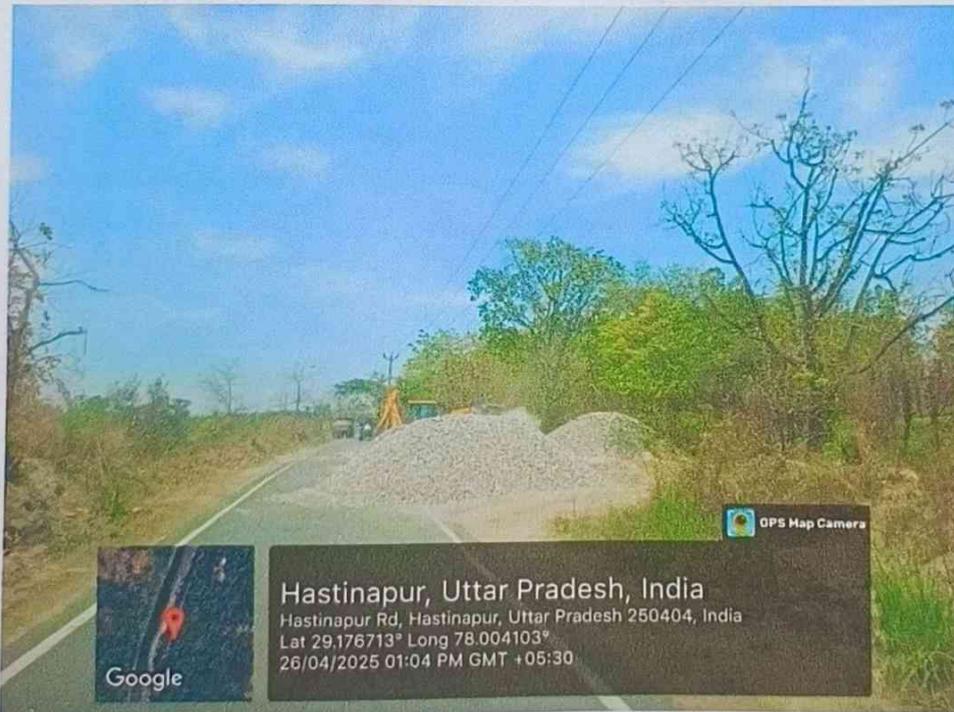


True Copy

[Handwritten signature]

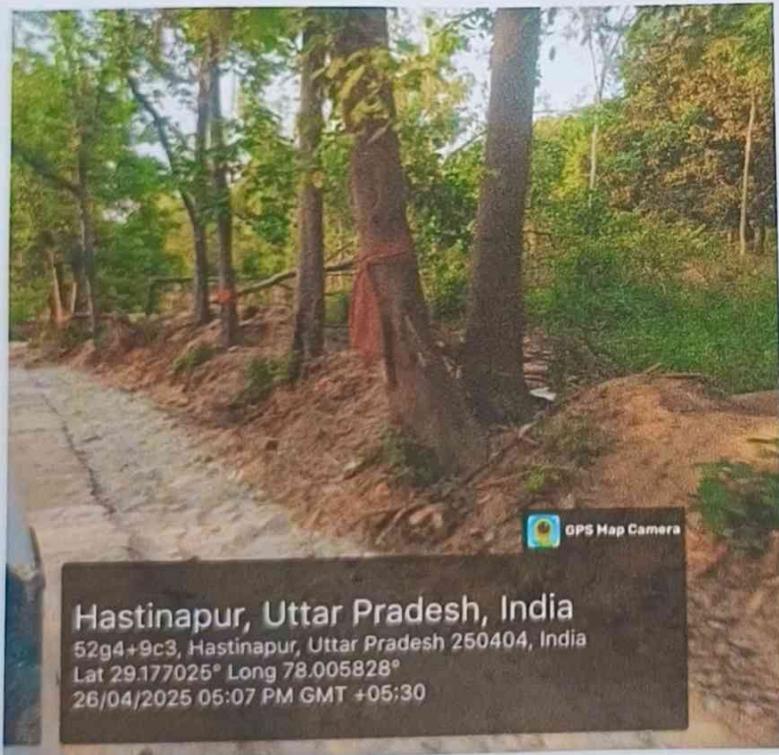
True Copy
[Handwritten signature]

5



True Copy

Rohit Kaul
True Copy
Rohit Kaul



True Copy

Ranjit Kaur
True Copy
Ranjit Kaur